

## भारतीय समाज में वैश्वीकरण का आर्थिक सामाजिक राजनीतिक और संस्कृतिक प्रभाव विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्राप्ति: 15.05.2024  
स्वीकृत: 26.06.2024

प्रो० निरंजना शर्मा  
राजनीति विज्ञान विभाग

29

राजकीय महाविद्यालय खाड़ी टिंगो  
ईमेल: dr.niranjanasharma@gmail.com

### सारांश

आधुनिक सम्यता में पुरुष एवं महिलाओं की उत्पादन क्षमताओं में उनके सामाजिक संबंधों और संस्थाओं ने आस-पास की दुनिया के बारे में सोचने के तौर तरीकों में असम्भावी परिवर्तन किया है। वैश्वीकरण एक जटिल और बहुआयामी घटना है यह विश्व के विचारों उत्पादों संस्कृति के अन्य पहलूओं के आदान-प्रदान के उत्पाद के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय एकीकरण प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय और सांस्कृतिक संसाधनों का विश्वव्यापी आदान प्रदान होता है। पिछले 03 दशकों में नवीन आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना उभारी है। उन्होंने राष्ट्रों के स्थान एवं भूमिका को सीमित किया है प्रौद्योगिक और सूचना तंत्र में परिवर्तनों ने परम्परागत धराणाओं को पूर्णता बदल दिया है वैश्वीकरण के विकास में योगदान देने वाले कई कारक प्रमुख हैं वैश्वीकरण के अर्थ में मतैक्य पाया जाता है कुछ विश्लेषक इसे यह सकारात्मक राजनीतिक आर्थिक और तकनीकी विकास का प्रयाय मनाते हैं किन्तु कुछ इसे आधिपत्य स्थानीय व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का आधार मानते हैं किन्तु वास्तव में वैश्वीकरण ने विश्व स्तर पर परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन किया है कि राज्य की शक्ति इसी आधार पर निर्धारित होने लगी है वैश्वीकरण के अन्तर्गत देश की अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ती है वस्तुतः 21वीं सदी में वैश्वीकरण के संकारत्मक आयामों से मानव जाति के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य प्राप्त करने का समोहिक प्रयास किया जा सकता है जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक चेतना के मानकों की उपलब्धता को सरल बनाया जा सकता है वैश्वीकरण का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक परिवृश्यों में पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इस प्रक्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन इस शोध पत्र में करने का प्रयास किया है।

वैश्वीकरण शब्द का उपयोग पिछले विषम 50 वर्षों में दुनिया के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो वैज्ञानिक क्रांति द्वारा माल, सेवाओं के एक विस्तारित अंतराष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय और भू-राजनीतिक सीमाओं के ह्लास के लिए त्वरित था। समाजशास्त्री, रोलैंड रॉबर्ट्सन के अनुसार "एक अवधारणा के रूप में

वैश्वीकरण दुनिया के संपीडन और समग्र रूप से दुनिया की चेतना की गहनता दोनों को संदर्भित करता है, दोनों ठोस वैश्विक अन्योन्याश्रयता और पूरे विश्व की चेतना है। **पीटर डिकेन** के लिए “वैश्वीकरण स्वाभाविक रूप से भौगोलिक है क्योंकि एक प्रक्रिया के लिए हमें रास्ते पर विचार करने की आवश्यकता होती है, अंतरिक्ष, स्थान और समय को तकनीकी, आर्थिक और राजनीतिक प्रथाओं में समकालीन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कॉन्फिगर और मान्यता प्राप्त है।” इस प्रकार वैश्वीकरण को विभिन्न पहलुओं में परिभाषित किया गया है। भूमण्डलीकरण सामाजिक संबंधों की संपूर्ण श्रृंखला को सुसंबद्ध रूप देता है। यह अपना प्रभाव जीवन के प्रत्येक पहलुओं पर डालता है। यद्यपि इन संबंधों का जोड़ एकसमान गति से नहीं मिलता। यह अत्यधिक विरूपता में भी फलित हो सकता है। इसमें भूमण्डलीय बाजारों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष और कुछ संगठनों में सत्ता का केन्द्रीकरण शामिल है। बहुराष्ट्रीय निगमों का उदय और अर्तराष्ट्रीय मुद्रा का (IMF), विश्व बैंक (B) व विश्व व्यापार संगठन (WTO) की नई भूमिका उसके साथी के रूप में आयी है। वै “वीकरण एक विकास की प्रक्रिया मानी जा सकती है जिसमें सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अदान-प्रदान, राष्ट्र-राज्य रूपी कृत्रिम सीमाओं एवं नियत्रण के कारण लोग एकल विश्व समाज के रूप में एकत्रित हो रहे हैं। भारत में भी मूल्यों संस्थाओं और विचारधाराओं में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। वैश्विक बाजार और व्यापार ने हमारी जीवन पद्धति, उपभोग के प्रतिमान और सांस्कृतिक उत्पादन को बाजार के माध्यम से बदल दिया है। आज भारतीय समाज एक उपभोग समाज का रूप ले रहा है। बिजली, सड़कों का जाल, संचार के साधन, खान-पान, पहनावा आदि सभी बदल रहे हैं। हरित क्रांति ने गाँव के लोगों को भी परिवर्तन की इस श्रृंखला में बाँध दिया है।

### विश्लेषण

विकासशील देशों के लिए इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हुए। इसके सकारात्मक प्रभावों से तो लाभ उठाना ही चाहिए नकारात्मक पक्षों पर सावधानी से विचार करके उसके दुष्प्रभावों को कम करना होगा। इस कार्य में शिक्षा प्रणालिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अंतराष्ट्रीय आर्थिक नीतियों को अपने राष्ट्रहितों और आवश्यकताओं के अनुकूल निर्मित करने में विकासशील देशों की भूमिका अत्यंत सीमित हो गई है। आज विकासशील देशों को न केवल भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा, अपेक्षित विकसित करने का विकल्प भी नहीं बचा है। 1930 के दशक में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन रॉबिन्सन और अमेरिकी अर्थशास्त्री एडवर्ड चैम्बरलिन ने स्पष्ट किया कि बाजारवादी तत्व के बाजार पर हावी होने से क्रेता-विक्रेता के हित सामान रूप से नहीं सधते। अगले दो दशकों के दौरान क्रीड़ा सिद्धात के उदय और उस पर आधारित सूचना एवं अनिश्चितता के आधुनिक सिद्धातों ने रेखांकित किया है कि अनेक बार बाजार के लेन-देन से समाज को अनुकूलतम परिणाम नहीं प्राप्त होते। अतः सरकार को बाजार और अर्थव्यवस्था में सक्रिय हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी कारण 1930 के दशक के पूँजीवाद देशों में राज्य की आर्थिक भूमिका बढ़ी तथा औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक स्वामित्व का विस्तार से उदित मिश्रित अर्थव्यवस्था का दबदबा 1970 के दशक के मध्य तक रहा। यह स्थिति सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की सीमाओं को निरंतर संयमित और नियंत्रित करती रही। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका अपेक्षाकृत

प्रभावकारी रही और नये उपक्रमों का निजी उद्यमों के राष्ट्रीयकरण से इसका विस्तार किया गया। हाल के वर्षों में हम देख रहे हैं कि उभरती हुई स्थानीय शक्तियाँ अपने मुददें भूमण्डलीय स्तर पर उठाने के प्रयास कर रही हैं, जिससे राष्ट्र-राज्य की शक्ति और प्रभावशीलता में कमी आई है। अब वैश्विक मुददों का राष्ट्रीयकरण हो गया है। राज्य के कई परम्परागत अधिकार उसके हाथों से निकलते जा रहे हैं। रक्षा, संचार और आर्थिक व्यवस्था आदि क्षेत्रों का समन्वय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा है। अब राष्ट्र राज्यों की प्रभुसत्ता बड़े राजनीतिक संगठन के साथ जुड़ गयी है। अब वैश्वीकरण से देश की राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों, जिनके चलते देश की स्वाधीनता पर आने वाले खतरे की बात की जाती है। धनी देशों के ही कई विद्वान अब स्पष्ट कहने लगे हैं कि वे "वीकरण के पहले दौर का इतिहास दोहराया जा रहा है। वे उपनिवेश बने, देशों की भारी आर्थिक तबाही हुई। भारत के बारे में ही कहा जाता है कि उपनिवेशी दौर के 120 सालों में 30 से ज्यादा भयानक अकाल देश को झेलने पड़े। 1996 के बंगाल के आकाल का जिक्र में ही 10 लाख से ज्यादा लोग मरे। अकाल का जिक्र यहाँ इसलिये किया गया कि उसमें सीधे खाद्यान्न की कमी से लोग मरते हैं। ध्यान दिया जा सकता है कि भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत के बाद भूख से होने वाली मौतों और कर्ज न चुका पाने वाले किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं की संख्या तेजी से बढ़ी है पहले के मुकाबले भुखमरी और आत्महत्या की इलाके भी बढ़े हैं। भारत में एक समूह मानता है कि बेरोजगारी और गरीबी उदारीकरण के बाद बदत्तर हुई है और दूसरे समूह का कहना है कि ऐसा नहीं है। पिछले 15 सालों में अधिकतर देशों में निम्न स्तरीय रोजगार के काफी मामले देखने को मिले, बेशक निम्न स्तरीय रोजगार से कम वेतन मिलता है। इसके अलावा बदलते राजेगार नमूनों का दूसरा नुकसान यह होता है कि श्रमिकों की सौदेबाजी की स्थिति कमजोर होती है, खासकर कम कुशलता वाले श्रमिकों की। गरीबी की समस्या का निपटारा व्यवितकरण आजकल विश्व-स्तरीय बाजारकरण से सिद्धांतों में भी अन्तर्निहित है। इसी मत की अभिव्यक्ति करते हुए विश्व बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष बुल्फेन्सोन्ह ने लिखा था कि— गरीबी मिटाना संभव है परन्तु अनिवार्य नहीं हैं। इसी मत को प्रगट करते हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक भूतपूर्व महामंत्री बुतरस बुतरस घाली ने कहा था कि—अतीत से सबक सीखने का अर्थ है जो शक्तियाँ कार्यरत हैं, हमें उन पर नियंत्रण करने के प्रयास बंद कर देने चाहिए।

भारत में भूमण्डलीकरण के कारण सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं। जिससे यूरोपीय और अमेरिकी संस्कृति को अपनाने की होड़ के साथ ही इनसे जुड़ी मुसीबतें भी बढ़ी हैं। आज विदेशी कम्पनियों को भारत एक बड़ा बाजार के रूप दिखाई देता है, क्योंकि आज यहाँ का मध्यवर्ग सूचना के आधुनिकतम उत्पादों से लैस है। आज उसकी स्थिति दस-पन्द्रह साल पहले की नहीं रह गई, वह आज साइबर जगत में भ्रमण करता है और टेलीविजन उसे देश-विदेश की हर नवीनतम घटना और उत्पाद की जानकारी पलक झपकते देता है। जिसके कारण यह सुबह उठने से लेकर रात्रि शयन तक निरंतर सूचनाओं से घिरा रहता है बल्कि उनसे प्रभावित भी होता है, फलस्वरूप वह भी भूमण्डलीय बाजार का एक उपभोक्ता बनने से खुद को रोक नहीं पाता है। इस संदर्भ में सच्चिदानंद सिन्हा कहते हैं कि— "दरअसल नई संचार क्रांति से ग्लोबल विलेज बनने की बजाय संसार ग्लोबल सुपर मार्केट बन गया है। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण

सर्वाधिक चर्चित प्रक्रिया है, आर्थिक रूप से संसार एक ईकाई बनता जा रहा है। एक देश की आर्थिक घटनाएँ अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने लगी हैं। अनेक प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक प्रक्रियाएँ अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीयकृत होती जा रही हैं।” इसमें प्रमुख क्षेत्र हैं— संचार, उत्पादन, व्यापार, वित्त एवं अन्य आर्थिक सहयोग के मामले। अब समस्त संसार में अभूतपूर्व रूप से व्यापार आदान—प्रदान होने लगा है। डॉलर, पाउण्ड, यूरो तथा येन जैसी मुद्राओं का चलन विश्वव्यापी हो गया है। इन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश द्वारा जारी धन प्राप्ति में विशेष अधिकार (Special Drawing Right -SDR) तथा यूरोपीय यूनियन द्वारा जारी मुद्रा का भी प्रमुख स्थान है। क्रेडिट कार्ड (Credit Card) के रूप में “प्लास्टिक मुद्रा” भी समस्त विश्व में स्वीकृत हो गई है तथा बैंकिंग व्यवस्था भी भूमण्डलीकृत हो गयी है।

### राजनीतिक प्रभावों का आकलन

भूमण्डलीकरण ने सत्ता की जवाबदोही और पारदर्शिता को मजबूत करके उसे सुशासन की ओर अभिमुख किया है। इसने राष्ट्र—राज्य की शक्ति का परिसीमन किया है। शासक सम्भानतों के विरोधियों एवं अलाभान्वित समूहों की आज की अधिक व्यापक विश्व में पहुँच हैं। वास्तव में अनेक असहमत विचारों एवं पक्ष समर्थक समूहों ने अपने प्रतिष्ठानों को आगे बढ़ाने के लिए भूमण्डलीकरण का प्रभावी प्रयोग किया है।

- भूमण्डलीकरण ने वर्ग संबंधों को बहुत प्रभावित किया है। सत्ता का पूँजी और विकसित विश्व की ओर विचलन तथा निर्णय लेने का अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों एवं सामूहिक पूँजी की एक गठजोड़ की ओर स्थानांतरण हुआ है। संगठित कामगार वर्ग की शक्ति का ह्वास हुआ है। भूमण्डलीकरण का सामाजिक—सांस्कृतिक पक्ष भी अनोखा कहा जा सकता है। विकासशील देशों में यह यिंता आम बात है कि वैश्वीकरण के आर्थिक लाभ मिलें न मिलें इसके सांस्कृतिक व सामाजिक दुष्परिणाम उन्हें झेलने पड़ेंगे। भारत जैसे देशों की न सिर्फ महानगरीय वरन् ग्रामीण आबादी भी इस सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की शिकार हो रही है। पिछले कुछ समय पर नजर डालें तो पायेंगे कि की राष्ट्र राज्य की सीमाएँ कहीं कमजोर हुई हैं तो कहीं मजबूत हुई है, तो कहीं पर तो एकीकरण की प्रकृति दिखाई देता है। **सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय** के नाम पर जो सिद्धांत चलाया जा रहा है वह वास्तव में विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश और विश्व व्यापार संगठन द्वारा वैश्वीकरण को अमली जामा पहनाया का एक प्रयास है।
- वैश्वीकरण का प्रभुत्वकारी रूप सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में देखा जा सकता है, लेकिन साथ ही यह राजनीतिक और आर्थिक वैश्वीकरण का आधार भी पुख्ता करता है। आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभुत्वकारी रूप भले ही आर्थिक क्षेत्र में प्रखरता से नजर आता हो, लेकिन इसके साथ ही यह लोगों के रहन—सहन, खान—पान और जीवनशैली में सामाजिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण को पुख्ता करता है। राजनीतिक वैश्वीकरण तो इन सभी प्रक्रियाओं के केन्द्र में है।

- शिक्षा किसी भी समाज को बन्धनों से मुक्त करके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला प्रमुख माध्यम होता है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों ने ज्ञान को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। जिज्ञासु मानव मस्तिष्क ने नवीनतम शोधों, उत्पादों और तकनीकियों को निरन्तर अद्यतन और उच्चता की ओर ले जाने का प्रयत्न किया है। किसी भी पिछड़ें समाज के शोषण का मुख्य कारण अशिक्षा को माना जाता है, चाहे उसके पास मौजूद हों, वह तब तक कर सकता, जब तक उसे विशिष्ट क्षेत्र का ज्ञान न हो। वैश्वीकरण का सार्वाधिक प्रमुख योगदान परिमार्जित विवेक को अबाधित रूप सम्पूर्ण विश्व में प्रसार-प्रचार करने से सम्बन्धित है शिक्षा संस्थानों के माध्यम से ज्ञान-विज्ञान का प्रसार होना संभव हुआ है। पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली समस्त संस्थाएं वैशिक प्रतिस्पर्धा में अद्यतन एवं प्रासंगिक बने रहना चाहती हैं। वैश्वीकरण ने भारतीय संघातक व्यवस्था में एक संकरमण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है इससे हमारी संवैधानिक व्यवस्था पर दबाव बना है अतः इस दबाव की दशा दिशा को समझना आवश्यक है। विकास के सामाजिक मानदण्ड की आर्थिक विकास व वैश्वीकरण को सतर्क गतिशील बनाया रखने में सहायक हो सकते हैं यदि सामाजिक मानदण्डों पर आगे नहीं बढ़ें तो विकास आधारहीन सिद्ध होने का खतरा उत्पन्न हो जायेगा। साथ ही शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक निजीकरण होने के कारण आम आदमी व मध्य वर्ग की पहुंच से ये सुविधा समाप्त होती जा रही है तथा इन सेवाओं के माध्यम से पूरी लागत वासूल करने की नीति गैर बराबरी को जन्म दे रही है। इन समस्त समस्याओं के समाधान हेतु आर्थिकहित, पुंजी-‘निवेश शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे वैशिक लोकतंत्र की अवधारणओं को विश्व स्तर पर ग्रमीण बैंक व सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक मदद हेतु निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर प्रदान किया जा सके।

#### सन्दर्भ

1. काबरा, कमल नयन. (2005). भूमण्डलीकरण विचार नीतियां और विकास. प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली।
2. सिंह, प्रेम. (2006). उदारीकरण की तनाशाही. राजकमल प्रकाशन: नई दिल्ली।
3. बोहरा, वन्दना. (2007). वैश्वीकरण में नागरिकता. ओमेगा पब्लिकेशन्स: नई दिल्ली।
4. भाटुडी, अमित., नायक, दीपक. (2008). उदारीकरण का सच. राजकमल प्रकाशन: नई दिल्ली।
5. मिश्र, गिरीश. (2012). निजीकरण के बढ़ते कदम. नीति मार्ग (पाक्षिक). भौपाल. 30 अप्रैल.  
14. अंक 14.